भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.02.2026 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2054 का उत्तर

नासिक में रेलवे अवसंरचना परियोजना

2054. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नासिक जिले में स्वीकृत, जारी निविदा, कार्यान्वयनाधीन/अनुमोदन के लिए लंबित रेल पारपथ (आरओबी), आरयूबी, समपार फाटक प्रणाली को समाप्त करने और अन्य सभी रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं (स्टेशन पुनर्निर्माण, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, साइडिंग, माल टर्मिनल, एफओबी, यार्ड आदि) का ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए स्वीकृति/अनुमोदन की तारीख, कार्यान्वयन एजेंसी, अनुमानित लागत, वर्तमान स्थिति और प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) विलंब के क्या कारण हैं और परियोजना को शीघ्र पूरा करने और सड़क-रेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध विशिष्ट उपाय, वित्तपोषण प्रतिबद्धताएं और अंतर-एजेंसी समन्वय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): 01.04.2025 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर नासिक जिले में 25 अदद् समपारों सहित 16,499 चौकीदार वाले समपार हैं। भारतीय रेल के बड़ी लाइन नेटवर्क पर सभी बिना चौकीदार वाले समपारों को 31.01.2019 तक समाप्त कर दिया गया है।

भारतीय रेल में ऊपरी/निचले सड़क पुल के निर्माण कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन कार्यों को गाड़ी परिचालन में संरक्षा और गतिशीलता पर इसके प्रभाव और सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है और शुरू किया जाता है।

भारतीय रेल में वर्ष 2004-14 की तुलना में वर्ष 2014-25 (दिसंबर 2025) की अवधि के दौरान निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार हैं:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (दिसंबर, 2025 तक)	13882 अदद (इसमें महाराष्ट्र राज्य के 1,228 अदद शामिल हैं)

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 1,14,298 करोड़ रुपए की लागत पर 4,769 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में 406 करोड़ रुपए की लागत पर 20 आरओबी/आरयूबी अदद शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों पर हैं।

रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुल कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) को अंतिम रूप देने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।

ii. ऊपरी/निचले सड़क पुलों कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं।

iii. डिजाइन के अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए स्पैन के विभिन्न संयोजन, तिरछापन और रेलवे के हिस्से पर सड़क की चौड़ाई के लिए अधिसंरचना नक्शों का मानकीकरण किया गया है। इसे सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए रेल लाइनों पर त्वरित योजना निर्माण हेतु अपनाया जा सकता है।

iv. रेलवे द्वारा ऊपरी/निचले सड़क पुल पुलों के कार्यों को जहां कहीं संभव हो एकल निकाय के आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहती है तो रेलवे उन्हें एकल निकाय के आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दे सकता है।

स्टेशन का पुनर्विकास:

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए महाराष्ट्र के नासिक जिले में आने वाले नासिक रोड, देवलाली, इगतपुरी, लासलगाँव, मनमाड जंक्शन, नगरसोल और नंदगांव रेलवे स्टेशन को चिह्नित किया गया है।

इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इस योजना में स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उन्हें चरणों में लागू करना शामिल है। प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लानिंग में शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार
- शहर के दोनों ओर के स्टेशनों का एकीकरण
- स्टेशन भवन का सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पानी बूथ में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप व्यापक पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप
- प्लेटफॉर्म सतह और प्लेटफॉर्म पर कवर का सुधार/प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमॉडल एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, भूदृश्य, आदि का प्रावधान।

इस योजना में दीर्घकाल में स्टेशन पर शहर के केंद्र के निर्माण, आवश्यकता, चरणबद्धता और व्यवहार्यता के अनुसार दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान आदि की भी परिकल्पना की गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया जा चुका है। इनमें से 132 स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
महाराष्ट्र	132	अहमदनगर, अजनी (नागपुर), अक्कलकोट रोड़, अकोला, आकुर्डी, अमलनेर, आमगाँव, अमरावती, अंधेरी, बडनेरा, बल्हारशाह, बांद्रा टर्मिनस, बारामती, बेलापुर, भंडारा रोड, भोकर, भुसावल, बोरीवली, भायखला, चालीसगाँव, चांदा फोर्ट, चंद्रपुर, चर्नी रोड, छत्रपति संभा जी नगर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, चिंचपोकली, चिंचवाड, दादर (मध्य रेल), दादर (पश्चिम रेल), दहिसर, दौंड, देहु रोड, देवलाली, धामणगांव, धरणगांव, धाराशिव, धर्माबाद, धुले, दिवा, दुधनी, गंगाखेर, गोधानी, गोंदिया, ग्रांट रोड, हडपसर, हातकणंगले, हजूर साहिब नान्देड, हिमायत नगर, हिंगनघाट, हिंगोली दक्कन, इगतपुरी, जलगाँव, जालना, जेऊर, जोगेश्वरी, कल्याण जंक्शन, कामटी, कांदिवली, कंजुर मार्ग, कराड, काटोल, केडगाँव, किनवट, कोपरगाँव, कुर्डुवाडी जंक्शन, कुर्ला जंक्शन, लासलगाँव, लातूर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, लोनंद जंक्शन, लोनावाला, लोअर परेल, मलाड, मलकापुर, मनमाड जं, मानवत रोड, मरीन लाइन्स, माटुंगा, मिराज जंक्शन, मुदखेड़ जंक्शन, मुंबई सेंट्रल, मुंब्रा, मुर्तिजापुर, नागरसोल, नागपुर जं, नंदगाँव, नांदुरा, नंदुरबार, नरखेड़ जंक्शन, नासिक रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, पाचोरा जंक्शन, पालघर, पंढरपुर, पनवेल जंक्शन, परभणी जंक्शन, परेल, परली वैजनाथ, परतूर, फलटाण, प्रभादेवी, पुलगाँव जंक्शन, पुणे जंक्शन, पूर्णा जंक्शन, रावेर, रोटेगांव, साईंनगर शिर्डी, सैंडहर्स्ट रोड, सांगली, सतारा, सावदा, सेलू, सेवाग्राम, शहाड, शेगांव, शिवाजी नगर पुणे, श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर, सोलापुर, तलेगांव, ठाकुर्ली, ठाणे, टिटवाला, तुमसर रोड, उमरी, उरुली, वडाला रोड, विद्याविहार, विक्रोली, वडसा, वर्धा, वाशिम, वाठार

महाराष्ट्र में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं। अब तक इस योजना के तहत नासिक जिले में देवलाली स्टेशन सहित 17 स्टेशनों (अमगाँव, चांदा फोर्ट, चिंचपोकली, देवलाली, धुले, केड़गांव, लासलगांव, लोणंद जंक्शन, माटुंगा, मुर्तिजापुर जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, परेल, सावदा, शहाड, वडाला रोड, बारामती और नांदुरा) का कार्य पूरा हो चुका है। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तीव्र गति से किए गए हैं और उपरोक्त स्टेशनों में से कुछ की प्रगति निम्नानुसार है:

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत महाराष्ट्र में शुरू किए गए कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार है:

नासिक रोड: नए 12 मीटर चौड़े पैदल पार पुल के प्रावधान, आवश्यकता के आधार पर मार्ग में सवारी डिब्बों में पानी की व्यवस्था, मेला टॉवर नियंत्रण केंद्र के प्रावधान, परिचलन क्षेत्र का विकास, चाहरदीवारी, प्लेटफॉर्म की सतह, 16 शौचालय ब्लॉकों के सुधार कार्य, दिव्यांगजनों के लिए शौचालय, साइनेज, फर्नीचर का प्रावधान, 6 मीटर चौड़े पैदल पार पुल का निर्माण, पूर्वी दिशा की नई इमारतों का निर्माण, परिचलन क्षेत्र और पार्किंग के विकास कार्य को मंजूरी दी गई है और कार्य आबंटित किए गए हैं। नई पूर्वी दिशा के स्टेशन भवन का निर्माण, परिचलन क्षेत्र एवं पार्किंग में सुधार और नए 6 मीटर चौड़े पैदल पार पुल के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है।

इसके अलावा, आरसीसी ओवरहेड टैंक, भूमिगत टैंक, नए पंप रूम, स्टेशन पर पानी की सुविधा में सुधार के लिए पाइपलाइन कार्य, नासिक रोड रेलवे स्टेशन का उन्नयन, मौजूदा पुराने पैदल पार पुल को हटाने, यात्री सूचना प्रणाली के प्रावधान के लिए कार्य और प्लेटफॉर्म संख्या 2, 3 और 4 पर प्लेटफॉर्म शेल्टर के प्रावधान के लिए कार्य को मंजूरी दी गई है।

इगतपुरी: नए सेवा भवन का संरचनात्मक कार्य, नए प्रवेश द्वार का निर्माण, पैदल पार पुल और स्वचालित सीढ़ियों पर कवर शेड, परिचलन क्षेत्र के लिए शेड, नए शौचालय ब्लॉक और सीवेज शोधन संयंत्र, नए बुकिंग कार्यालय के निर्माण का कार्य, स्टेशन की ऊंचाई और प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। समापन कार्य और सेवा भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

लासलगांव: नए बुकिंग कार्यालय के निर्माण, परिचलन क्षेत्र और पार्किंग में सुधार, प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान, नए प्रवेश द्वार, चाहरदीवारी का निर्माण, शौचालय, दिव्यांगजन सुविधाओं में सुधार और स्टेशन भवन में कमरों के नवीनीकरण का कार्य पूरा हो गया है। इसे पूरा करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

मनमाड: नए प्लेटफॉर्म शेल्टरों का प्रावधान, स्टेशन भवन के नवीनीकरण, शौचालयों और बुकिंग कार्यालय के नवीनीकरण का कार्य पूरा हो गया है। प्रवेश द्वार के मेहराब का निर्माण, परिचलन क्षेत्र और पार्किंग में सुधार, साइनेज और 12 मीटर फुट पैदल पार पुल के प्रावधान के लिए कार्य शुरू किए गए हैं।

भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/उन्नयन एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकता के अनुसार, प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अध्यधीन किए जाते हैं। कार्यों को मंजूरी देते समय और निष्पादित करते समय स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए उच्च कोटि के स्टेशनों को निम्न कोटि के स्टेशनों पर प्राथमिकता दी जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण आम तौर पर योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के तहत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के तहत आबंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि स्टेशन-वार या जिला-वार या

राज्य-वार। नासिक जिला मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,201 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का आबंटन किया गया है और अब तक 1,871 करोड़ रुपए का व्यय (दिसंबर, 2025 तक) उपगत किया गया है।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ एवं उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

नई लाइन/दोहरीकरण/आमान परिवर्तन कार्य:

पिछले पांच वर्षों के दौरान बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले सहित पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,171 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष
2025-26	23,778 करोड़ रुपए (20 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और वर्ष 2014-25 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले सहित पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने संबंधी कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	292 किलोमीटर	58.4 किलोमीटर प्रतिवर्ष
2014-25	2,292 किलोमीटर	208.4 किलोमीटर प्रतिवर्ष (3 गुना से अधिक)

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली 89,780 करोड़ रुपए की लागत पर कुल 5,098 किलोमीटर लंबाई की 38 परियोजनाओं (11 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 25 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है। इसका सार निम्नानुसार है:-

कोटि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च, 2025 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	11	1,355	234	10,504
आमान परिवर्तन	02	609	334	4,286
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	25	3,134	1,792	24,617
कुल	38	5,098	2,360	39,407

नासिक जिले में रेल संपर्कता को बेहतर बनाने के लिए, निम्नलिखित सर्वेक्षण पूरे किए गए हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है:-

1. कसारा-नासिक-मनमाड तीसरी और चौथी लाइन (131 कि.मी.)

2. नासिक-साईनगर शिरडी नई लाइन (95 कि.मी.)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बाद, परियोजना की मंजूरी के लिए नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि का मूल्यांकन द्‌वारा राज्य सरकारों और आवश्यक अनुमोदन सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है।

विद्‌युतीकरण

भारतीय रेल पर रेल नेटवर्क का विद्‌युतीकरण मिशन मोड में किया गया है। अब तक, लगभग 99.4% बड़ी लाइन नेटवर्क का विद्‌युतीकरण किया जा चुका है। शेष नेटवर्क में विद्‌युतीकरण का कार्य शुरू किया गया है। 2014-25 के दौरान और 2014 से पहले किया गया विद्‌युतीकरण निम्नानुसार है:

अवधि	मार्ग किलोमीटर
2014 से पहले (लगभग 60 वर्ष)	21,801
2014-25	46,900

नासिक जिले में, संपूर्ण मौजूदा बड़ी लाइन नेटवर्क का विद्‌युतीकरण किया गया है। इसके अलावा, सभी नई लाइन/बहुपथन परियोजनाओं को विद्‌युतीकरण के साथ मंजूरी दी जा रही है और उनका निर्माण किया जा रहा है।

यार्ड रीमॉडलिंग परियोजनाएं

नासिक जिले में रेल नेटवर्क की क्षमता में सुधार लाने के लिए, निम्नलिखित क्षमता वृद्‌धि कार्य किए गए हैं:

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	लागत (रुपए में)
1	नासिक रोड - माल शेड सीढ़ी को स्थानांतरित करके प्लेटफार्म-1 को 22 से 24 सवारी डिब्बों की लंबाई तक बढ़ाने के लिए यार्ड का पुनर्निर्माण।	17.68
2	नासिक रोड - अतिरिक्त स्टेब्लिंग लाइनों का प्रावधान	26.02
3	नासिक रोड - डाउन दिशा में दो स्टेबलिंग लाइनों का प्रावधान।	4.95

4	देवलाली - अतिरिक्त प्लेटफॉर्म के प्रावधान के लिए यार्ड का पुनर्निर्माण।	49.83
5	देवलाली - सी एंड डब्ल्यू जाँच और स्टेबलिंग की सुविधा का प्रावधान।	48.52
6	देवलाली-अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइनों का प्रावधान।	36.61
7	ओढ़ा - अतिरिक्त यात्री प्लेटफॉर्म के प्रावधान के लिए यार्ड का पुनर्निर्माण।	49.92
8	ओढ़ा - लंबी दूरी की सुविधाओं के प्रावधान के लिए यार्ड का पुनर्निर्माण।	32.70
9	ओढ़ा- स्टेबलिंग लाइनों का प्रावधान।	62.18
10	खेरवाडी स्टेशन - अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्मों के प्रावधान के लिए यार्ड का पुनर्निर्माण।	44.86
11	खेरवाड़ी - अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइनों का प्रावधान।	25.57
12	कस्बे सुकेणे -अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्मों के प्रावधान के लिए यार्ड का पुनर्निर्माण।	43.45
13	कस्बे सुकेणे - अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइनों का प्रावधान।	26.49
14	निफ़ाड - अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइनों का प्रावधान।	32.76
15	उगांव - लूप लाइन और स्टेबलिंग लाइनों प्रदान करना।	38.64
16	उगांव: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) का प्रावधान।	20.61

साइडिंग/फ्रेट टर्मिनल

महाराष्ट्र राज्य में माल परिवहन में सुधार लाने के लिए, 09 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों (जीसीटी) को पहले ही चालू किया जा चुका है, इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य (जिसमें नासिक जिले में कस्बे सुकेणे स्टेशन पर 1 परियोजना शामिल है) में 20 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों (जीसीटी) की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ।

******